भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2324
उत्तर देने की तारीख-04/08/2025

ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना

†2324. श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए हैं;
(ख) यदि हाँ, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई ऐसी पहलों का ब्यौरा क्या है;
(ग) ग्रामीण भारत में कितने स्कूलों में कार्यात्मक इंटरनेट और डिजिटल बुनियादी ढांचे तक पहुँच है;
(घ) क्या शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण उपकरणों और प्लेटफार्मों के उपयोग में प्रशिक्षण प्रदान करने की योजना है; और
(ङ.) सरकार का ग्रामीण स्कूलों में 100 प्रतिशत डिजिटल पहुँच सुनिश्चित करने का लक्ष्य प्राप्त करने की समय-सीमा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ.): शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची का हिस्सा है और अधिकांश सरकारी स्कूल राज्य सरकार और उसके निकायों के अधीन हैं। शिक्षा मंत्रालय, ग्रामीण क्षेत्रों सहित देशभर के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु समग्र शिक्षा के अंतर्गत आईसीटी और डिजिटल पहलों को क्रियान्वित करता है। इन पहलों का उद्देश्य शिक्षण और अधिगम प्रक्रियाओं में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करके शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना है। इन पहलों के तहत, वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) में प्रस्तुत राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार

आईसीटी प्रयोगशाला और स्मार्ट कक्षा स्थापित करने के लिए निधि प्रदान की जाती है। आईसीटी योजना के तहत दो विकल्प प्रदान करती है:

1. विकल्प I: ऐसे स्कूल जिनके पास पहले से आईसीटी सुविधाएँ नहीं हैं, वे आईसीटी लैब या स्मार्ट कक्षा चुन सकते हैं। 700 से ज़्यादा छात्रों वाले स्कूलों को एक अतिरिक्त आईसीटी प्रयोगशाला मिल सकती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हार्डवेयर, सॉफ़्टवेयर, टैबलेट, लैपटॉप और प्रशिक्षण संसाधन, डिजिटल बोर्ड, वर्चुअल क्लासरूम और डीटीएच चैनल खरीद सकते हैं।

2. विकल्प II: मौजूदा आईसीटी सुविधाओं वाले स्कूल योजना मानदंडों के तहत स्मार्ट कक्षाओं या टैबलेट का उपयोग कर सकते हैं।

दिनांक 17 मई, 2020 को आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल शुरू की गई, जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित सभी प्रयासों को एकीकृत करती है ताकि देशभर में शिक्षा तक एक से अधिक मोड में पहुँच सुनिश्चित की जा सके। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी आवश्यकताओं के अनुसार इन पहलों के उपयोग, निगरानी और प्रभावशीलता के मूल्यांकन के लिए एनसीईआरटी के साथ सहयोग करते हैं। एनसीईआरटी इन पहलों की गुणवत्ता पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित मार्गदर्शन/प्रतिक्रिया भी प्रस्तुत करता है।

पीएम ई-विद्या के प्रमुख घटक डिजिटल साक्षरता को बढ़ाने के लिए भी अनुकूलित हैं और इसमें 200 डीटीएच टीवी चैनल शामिल हैं। माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा इन चैनलों का शुभारंभ 9 मार्च 2024 को किया गया था। वित्तीय वर्ष 2022-23 की केंद्रीय बजट घोषणा के अनुसार, 12 डीटीएच चैनलों का विस्तार करके 200 पीएम ई-विद्या डीटीएच टीवी चैनल और 400 रेडियो चैनल कर दिए गए हैं ताकि सभी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र कक्षा 1-12 के लिए विभिन्न भारतीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान कर सकें। ये चैनल राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों और स्वायत्त निकायों को आवंटित किए गए हैं। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को क्षेत्रीय/स्थानीय भाषाओं में सामग्री बनाने और प्रसारित करने का अधिकार दिया गया है।

ज्ञान साझाकरण हेतु डिजिटल अवसंरचना (दीक्षा) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूल शिक्षा के लिए गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री और सभी कक्षाओं के लिए क्यूआर कोड वाली सक्रिय पाठ्यपुस्तकें (ईटीबी) (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म) उपलब्ध कराने हेतु राष्ट्र का डिजिटल अवसंरचना है। कुल मिलाकर, छात्रों, शिक्षकों और अन्य हितधारकों द्वारा दीक्षा पर 564.05 करोड़

शिक्षण सत्र पूरे किए जा चुके हैं। महत्वपूर्ण आलोचनात्मक चिंतन कौशल को बढ़ावा देने और रचनात्मकता को बढ़ावा देने के लिए, दीक्षा प्लेटफ़ॉर्म पर 300 से अधिक वर्चुअल लैब बनाए और उपलब्ध कराए गए हैं।

सभी माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों को आईसीटी लैब और स्मार्ट कक्षा से परिपूर्ण करने के लिए, 28 मई 2025 को एक पूरक परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की बैठक आयोजित की गई। कुल 20,456 आईसीटी लैब और 29,896 स्मार्ट कक्षा को मंजूरी दी गई है, जिसमें आईसीटी लैब के लिए 911.13 करोड़ रुपये और समग्र शिक्षा के अंतर्गत स्मार्ट कक्षा के लिए 630.38 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति शामिल है, इसके अलावा 1,56,213 आईसीटी लैब और 1,46,040 स्मार्ट कक्षा को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा, केंद्रीय बजट 2025 में भारतनेट परियोजना के तहत बीएसएनएल के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी माध्यमिक विद्यालयों तक ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का विस्तार करने का प्रावधान भी शामिल है।

एनसीईआरटी, शिक्षण, अधिगम और मूल्यांकन हेतु डिजिटल तकनीक और आईसीटी के उपयोग में शिक्षकों की दक्षता संवर्धन हेतु सक्रिय रूप से वेबिनार और ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित कर रहा है। वर्ष 2020 से अब तक, डिजिटल उपकरणों, आईसीटी एकीकरण और साइबर सुरक्षा पर केंद्रित 1,146 से अधिक वेबिनार आयोजित किए जा चुके हैं। ईटी और आईसीटी पर एनईपी 2020 की सिफारिशों और ई-सामग्री के विकास पर ऑनलाइन प्रशिक्षण श्रृंखला भी आयोजित की जाती है। अक्टूबर 2021 से साइबर सुरक्षा पर नियमित मासिक प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिससे 2022 और 2025 के बीच 8 लाख से अधिक शिक्षार्थी लाभान्वित हुए हैं। इसके अतिरिक्त, दीक्षा प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिक्षकों और शिक्षाविदों के लिए सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) पाठ्यक्रम भी उपलब्ध कराए जाते हैं, जो एनईपी 2020 के अनुरूप हैं।

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने भी केंद्र प्रायोजित समग्र शिक्षा योजना के तहत निष्ठा - स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल नामक एक एकीकृत शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर अधिगम परिणामों में सुधार के लिए एक राष्ट्रीय पहल शुरू की है।

*****